



Press Release, June 30, 2022

प्रेस विज्ञप्ति, 30 जून 2022

सिडबी और ग्रांट थॉर्नटन भारत (परियोजना प्रबंध इकाई) द्वारा एमएसएमई पारितंत्र के विकास पर राष्ट्रीय स्तर की ज्ञानशाला (लर्न शॉप) का आयोजन
National Level Learn-shop on development of the MSME ecosystem organised by SIDBI & Grant Thornton Bharat (its PMU)

आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के साथ संरेखित करते हुए सिडबी ने अपनी परियोजना प्रबंध एजेंसी ग्रांट थॉर्नटन (GT) के सहयोग से 30 जून 2022 को एमएसएमई पारितंत्र के विकास पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला (वर्चुअल कार्यक्रम) का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्लस्टर केंद्रित विकास के लिए संरेखित अच्छी प्रथाओं को सीखना और साझा करना तथा इस प्रकार उसे अंगीकार करते हुए अपने को अधिकतम रूपांतरित करना था।

Aligned to AKAM celebrations, SIDBI along with its Project Management agency Grant Thornton (GT) , organized on 30th June 2022, a National Level "Learn-shop" (Virtual programme) on development of the MSME ecosystem. The objective was to learn and share good practices aligned to cluster centric development thus maximizing adoption and adaptation.

सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस रमण द्वारा मुख्य वक्तव्य दिया गया। उन्होंने कहा कि "उद्यम विकास मॉडल में जीवंतता बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि सिडबी ने क्लस्टर विकास विषय को प्राथमिकता दी है, लेकिन केवल हितधारकों जो कि प्रमुख रूप से राज्य सरकारें हैं, उनके साथ समन्वय में ही टिकाऊ कार्यनीति विकसित की जा सकती है। उन्होंने सभी हितधारकों से देश में एमएसएमई पारितंत्र के समग्र विकास के लिए एक साथ चलने का आह्वान किया।

The keynote was delivered by Shri S. Ramann CMD, SIDBI, who said that there is need to keep vibrancy in enterprise development models. He mentioned that SIDBI has prioritized cluster development theme but can only evolve sustainable strategy in coordination with stakeholders, key being state governments. He called upon all stakeholders to walk together for overall development of the MSME ecosystem in the country.

इससे पहले, 20 से अधिक राज्य सरकारों के प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, श्री वी सत्य वेंकट राव उप प्रबंध निदेशक ने राज्य सरकारों के सहयोग से उद्यम मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में सिडबी की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने सिडबी क्लस्टर विकास निधि योजना के बारे में भी प्रकाश डाला जो एमएसएमई क्लस्टर अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के परामर्शदाता प्रो वी पद्मानंद, ग्रांट थॉर्नटन भारत के भागीदार ने पीएमयू (ग्रांट थॉर्नटन भारत) की तैनाती के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों

के साथ सिडबी के जुड़ाव के परिणामस्वरूप विकसित किए गए प्रमुख हस्तक्षेपों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में विस्तार से बताया। सम्मानित अतिथि, श्री डीके सिंह, आईएएस, महासचिव, एनएचआरसी ने एमएसएमई पारितंत्र में मौजूदा अंतराल और इसे दूर करने के साधनों और तरीकों पर चर्चा की।

Earlier, while welcoming participants from over 20 state governments, Shri V. Satya Venkata Rao DMD illustrated SIDBI's role in strengthening the enterprise value chain in cooperation with state governments. He also highlighted about SIDBI Cluster Development Fund Scheme which is supporting State Governments for building MSME Cluster Infrastructure. Furthermore, Prof. V. Padmanand, Partner, Public Sector Consulting, Grant Thornton Bharat elaborated on the key interventions and best practices evolved as a result of SIDBI's engagement with various state governments/UTs through the deployment of PMU (Grant Thornton Bharat). The Guest of Honor, Shri D.K. Singh, IAS, Secretary General, NHRC spoke on the existing gaps in the MSME ecosystem and the means and ways to bridge the same.

पैनल चर्चा में शामिल विषय इस प्रकार हैं: एमएसएमई के लिए उपयुक्त ऋण उत्पाद-समूह; आधारभूत अवसंरचना /सिडबी क्लस्टर विकास निधि-एससीडीएफ के लिए राज्य /भारत सरकार की योजनाओं का सम्मिलन; एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए नीतियां और योजनाएं, सेवा प्रदाताओं का अभिग्रहण; राज्य स्तरीय लाइन विभागों और उद्योग संघों के डिजिटलीकरण और संस्थागत क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्तिकरण (क्लस्टर विकास, भारत सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ाव, प्रौद्योगिकी व्यवसाय विकास सेवाएं)।

The themes of the Panel Discussion included: Apt credit instruments for MSMEs; convergence of State/ GoI Schemes for hard infrastructure/ SIDBI Cluster Development Fund -SCDF;; Policy & Schemes to strengthen the MSME Ecosystem, Procurement of service providers; empowering through digitization Institutional capacity building of line departments and Industry Associations as the state level (Cluster development, twinning with GoI Schemes, Technology Business Development Services).

कुछ राज्य मिनी क्लस्टर विकास योजनाओं पर बल दे रहे हैं, जिससे सूक्ष्म और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा मिल रहा है। कतिपय राज्यों ने राज्य स्तरीय ऋण गारंटी निधि विकसित की है। डिजिटलीकरण पर आधारित सत्रों में इस आशय की पुष्टि हुई कि इससे एक व्यापक औद्योगिक अनकूलता का सृजन हुआ है और इसके माध्यम से ऋण तथा गैर वित्तीय सेवाओं की पहुंच को और भी अधिक गहन बनाया जा सकता है। राज्य असेवित /अविकसित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां एससीडीएफ जैसी योजनाएं एमएसई-सीडीपी की पूरक हैं और अन्य भारत सरकार पीपीपी आधारित योजनाएं अमूल्य समर्थन से लाभान्वित हो सकती हैं। संक्षेप में, आने वाले समय में समूहों के माध्यम से सहयोजन और संपर्क एवं समेकन प्रमुखता से अस्तित्व में बने रहेंगे। इसे राज्य स्तरीय मूल्य श्रृंखला के रूप में कार्यरत संस्थाओं के क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में एक ऐसा महत्वपूर्ण लिंक माना जाता है, जो पहले उपलब्ध नहीं था। एमएसएमई के लिए उपलब्ध राज्य, केंद्रीय और संस्थागत लाभों के प्रभावी वितरण के लिए सभी हितधारकों की डिजिटल क्षमता का निर्माण महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में चिह्नित किया गया। तमिलनाडु ने सिडबी के नेतृत्व में स्थापित सीजीटीएमएसई मॉडल, ट्रेड्स और पीएसबी59 प्लेटफॉर्म जैसे कतिपय मंचों का लाभ उठाकर एमएसएमई क्षेत्र के लिए अपने एकीकृत अभिगम मॉडल के माध्यम से प्रतिभागियों को शामिल किया। एमएसईसीडीपी, स्फूर्ति की केंद्र सरकार की योजनाओं के सम्मिलन

और एमएसएमई समूहों के समग्र विकास के लिए सिडबी एससीडीएफ का लाभ उठाने के महत्व पर पैनल में शामिल वक्ताओं द्वारा प्रकाश डाला गया। वित्तीय संस्थानों ने कच्चे माल के बैंकों और क्लस्टर आधारित वित्तीय साधनों की स्थापना पर कई राज्य सरकारों की पहल से सीखने वाले क्लस्टर आधारित वित्तीय उत्पादों के संबंध में प्रमुखता से चर्चा की।

Few states are laying thrust on mini cluster development schemes thus fostering micro and rural enterprises. Some have evolved state level credit guarantee funds. Sessions on digitization validated that it's a great enabler and can deepen the access of credit and non financial services. States are focusing on unserved/underdeveloped areas where SCDF like schemes complementing MSE-CDP and other Gol PPP based schemes can benefit from valuable support. In brief convergence, connect and consolidation through clusters shall be mainstay in the coming times. Capacity building of state level value chain actors is identified as crucial missing link. Building digital capacity of all stakeholders for effective delivery of available state, central and institutional benefits for MSMEs were identified as crucial connect. Tamil Nadu took the participants through its integrated access model for MSMEs by leveraging CGTMSE model, platforms such as TREDIS and PSB59 platform set up under leadership of SIDBI. Importance of convergence of Central Govt schemes of MSECDP, SFURTI and leveraging SIDBI SCDF for overall development of MSME clusters was highlighted by panelists. Financial Institutions mentioned about their thrust on cluster based financing instruments learning from the initiatives of many state governments on establishing raw material banks and cluster based financial instruments.

सिडबी ने स्वावलंबन संपर्क केंद्र पर अपनी पहलकदमियों के संबंध में सदन को अवगत कराया, जहां 100 जिलों में युवाओं के उद्यमों के सपनों को साकार करने में सहायता प्रदान की जा रही है। सिडबी ने राज्यों को अपने परिचालन कार्यालयों के माध्यम से ऋण संबंधी पहुंच के लिए शुरू से लेकर अंत तक किए गए आद्योपांत समाधान प्रबंध और क्लस्टर केंद्रित, सन्निहित-हरित उद्यम विकास को प्राथमिकता देने के बारे में भी अवगत कराया।

SIDBI apprised about its initiative on Swavalamban Connect Kendra where handholding to youths for converting dreams into enterprise is being facilitated in 100 districts. SIDBI also apprised states about its end to end solution on credit access through its operating offices and its prioritizing the cluster centric, green embed enterprise development.

पैनलिस्ट के रूप में कार्य करने वाले एमएसएमई पारितंत्र डोमेन में कुल 28 विख्यात विशेषज्ञों के अलावा, श्री डीपीएस खरबंदा, आईएएस - निदेशक, तकनीकी शिक्षा और पूर्व निदेशक, उद्योग, पंजाब सरकार, श्री एंथनी डी सा, आईएएस - पूर्व मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार तथा श्री मीनाक्षी सुंदरम, आईएएस - असम के माननीय राज्यपाल के सचिव व असम सरकार के पूर्व उद्योग आयुक्त ने देश में एमएसएमई परिदृश्य को बदलने के लिए विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं पर बतौर विशेषज्ञ अपनी वैचारिक निविष्टियाँ प्रदान कीं। उद्योग और 20 राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस अग्रणी कार्यक्रम में भाग लिया।

In addition to total 28 distinguished experts in MSME ecosystem domain who served as the panelists, distinguished personalities including Shri DPS Kharbanda, IAS – Director, Technical Education and former Director of Industries, Government of Punjab, Shri Anthony De Sa, IAS – Former Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh and Shri Meenakshi Sundaram, IAS – Secretary to Hon'ble Governor of Assam and former Commissioner of Industries, Government of Assam provided their expert inputs on best practices evolved for transforming MSME landscape in the country. Representatives of industry and government from 20 states attended the pioneering programme.